Paper – MPOLCC-7
MA (Sem-II)

Pol. Science

Dr. S. B. Kumar

Post-Cold War Issues (शीत युद्धोत्तर मुद्दे)

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वभाव से प्रगतिशील (progressive) है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर घटित होने वाली घटनाओं में कुछ घटनाएँ सामान्य होती है जबकि कुछ इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें इतिहास को मोड़ देने वाला कहा जा सकता है। इस प्रकार की एक ऐतिहासिक घटना थी 1989-90 में शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहे शीत युद्ध की समाप्ति ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नये युग का सूत्रपात किया। प्रत्यक्ष सैनिक संघर्ष की संभावना तो पहले ही समाप्त हो गई थी, फिर भी स्थायी ~~शांति~~ एवं टिकाऊ शांति संसार के लिए स्वप्न मात्र थी। आज शांति के लिए नए खतरे बड़े पैमाने पर उभर रहे हैं, जो संपूर्ण मानव सभ्यता के आधार के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में आई क्रांति ने कुछ लोगों के भविष्य को ~~अंधकार~~ प्रकाशमय बनाया लेकिन साथ ही निर्धन एवं अल्पविकसित देशों की स्थिति दयनीय ही बनी हुई है। अतः आज अधिक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है जो दुनिया में शांति, ~~विकास~~ सतत विकास (sustainable development), पर्यावरण की रक्षा का वाहक (agent) बन सके। दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक, अंत॰ मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समक्ष स्वायत्तता, जवाबदेही तथा प्रभावीपन (effectiveness) की नई चुनौतियाँ सामने आई है।

जैसा कि विदित है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात वैश्विक व्यवस्था द्विध्रुवीय से एकध्रुवीय हो गई है जिसमें अमेरिका (U.S.A.) अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर आसीन है। वह एकमात्र विश्व नेता अथवा विश्व पुलिसमैन की भूमिका निभा रहा है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व-व्यवस्था (World Order) में नयी ~~मुद्दे उभर~~ विशेषताओं के साथ प्रकट होती है जो इस प्रकार है:

1.) भूमण्डलीकरण (Globalisation) – ~~इसके अंतर्गत एक देश~~

2.) ~~उदा~~ उदारीकरण (Liberalisation) — व्यापार हेतु राष्ट्रों द्वारा कानूनी प्रतिबंधों में ढील देना जिससे आयात-निर्यात

Scanned with CamScanner

आसान हो सके।

3.) बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था (Market Economy) – इसे पूँजीवादी मॉडल भी कहा जाता है। इसकी विशेषता है – मुक्त व्यापार, खुली प्रतियोगिता खुले बाजार तथा उपभोक्तावाद (consumerism), आर्थिक क्षेत्र में राज्य का न्यूनतम नियंत्रण और निजीकरण।

4.) सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) – इसने विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। सूचना क्रांति ने वाणिज्य, उद्योग, प्रशासन, राजनय, अंत० संबंध आदि की कार्यप्रणाली में बदलाव लाकर समूचे विश्व को भूमंडलीय गांव (Global village) बना दिया है।

5.) सांस्कृतिक पहचान के नाम पर विश्व-व्यवस्था की पुनर्रचना (Reconfiguration of the World-Order on the basis of Cultural Identity) – नई विश्व व्यवस्था में सभ्यताओं का संघर्ष विश्व शांति के लिए बड़ी चुनौती है।

6.) विश्व व्यापार संगठन की उदीयमान भूमिका (Emerging Role of WTO) WTO के अंतर्गत जिस अंत० अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNC) के अधिकार और कार्यक्षेत्र अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रहे हैं जिसके कारण छोटे-छोटे उद्यमियों में रोष है।

7.) आर्थिक कारकों की निर्णायक भूमिका (Economic factors) – शीत युद्ध के दरम्यान विश्व व्यवस्था के निर्धारक सैनिक कारक थे जबकि वर्तमान में इनका स्थान आर्थिक कारकों ने ले लिया है। आज विश्व में शस्त्रों के स्थान पर डॉलर, पाउंड, युआन इत्यादि टकरा रहे हैं। सैनिक संधियों की जगह आर्थिक गुटबंदियों (जैसे, आसियान, एपेक साफ्टा, G-20, G-24) इत्यादि का बोलबाला है।

इस प्रकार नई विश्व व्यवस्था (शीत युद्धोत्तर काल) के जो विचारणीय मुद्दे हैं वो इस प्रकार हैं :

1.) मानवाधिकार (Human Rights)
2.) विकास का अधिकार (Right to Development)
3.) विश्व व्यापार (World Trade)
4.) पर्यावरण संरक्षण (Environment)
5.) उत्तर-दक्षिण संवाद (North-South dialogue) – यहाँ उत्तर से अर्थ अमीर एवं दक्षिण से अर्थ गरीब देशों से है।
6.) निःशस्त्रीकरण (Disarmament) – विशेषरूप से आण्विक शस्त्रों के संबंध में)
7.) अंत० आतंकवाद (Int. Terrorism)
8.) गरीबी उन्मूलन (Poverty eradication)
9.) बच्चों की कुपोषण से रक्षा (Protection of Child from malnutrition)
10.) प्रौद्योगिकी स्थानांतरण (Technology Sharing)
11.) आर्थिक राजनय (Economic diplomacy)
12.) संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण (Democratization of UN)
13.) अंत० वित्तीय संस्थानों का लोकतंत्रीकरण (Democratization of Int. Funding Agency) WB, IMF etc.

Scanned with CamScanner